

जल एवं उसका उपयोग

भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जल का बाहुल्य भी है तो उसका आभाव भी है। ज्यादा हिस्सा ऐसा है जहाँ आभाव है। जैसा कि हर क्षेत्र में भारत की बितरण प्रणाली दोष पूर्ण है। पानी के मामले में यह तथ्य प्रत्यक्ष देखा जाता है। एक स्थान ऐसा है जहाँ संसार की सबसे ज्यादा वर्षा होती है 12,500 ml सालभर होती रहती है तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ कई सालों में कभी कभी होती है फिर भी दोनों जगहों पर आबादी है और अपना अपना काम चला रही है। हर शहर जहाँ पाईपो से पानी घरों में पहुँचता है इतनी पानी की कमी है कि पुरे दिन में दो या चार घंटों की अपूर्ति होती है। कुछ शहरों में पानी के नल तो हैं पर पानी टैंकरो से ही आता है या खरीदना पड़ता है। पानी का व्यापार देखना है तो गुजरात व तमिल नाडू में देखें जितना चाहे पानी खरीदे और खर्च करें। पानी सरकारी महकमों को नहीं मिलता पर इन बेचने वालों को कहाँ से मिलता है उपर बाला ही जाने पर हमें मंत्त मालूम है सरकार देगी तो चोरी भी करेंगे या मुफ्त लेगें बरना धन्धे वाले को धन्धा क्यों न दें।

हम सब लोग मिलकर टकराव कर सकते हैं सरकार के साथ कि पानी का राष्ट्रीयकरण न किया जाय परन्तु क्या हम बड़े शहरों को या बड़ी कम्पनियों को पानी की चोरी से रोक सकते हैं क्या? जो पैसे की ताकत से पानी को खरीद या बेच रहे हैं। क्योंकि प्रान्तों की व शहरों की सरकारें इसमें भागीदार हैं अनयथा इन प्रान्तों की राजधानी में रहने वाले नेताओं की पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है कैसे पूरी होगी? आज भी हम मल्टी नेशनलस को अपने पानी के अथर्व व्यय से नहीं रोक पा रहे हैं जो कोका कोला पैप्सी कोला और प्रसाधन संस्थानों में बोतलों को साफ करने में ही खर्च हो रहा है। बोतलों में भर कर में ही बेचा जा रहा है हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊँ बली कहावत चरितार्थ हो रही है। पर क्योंकि इसमें कितने ही लोगों की जीविका चल रही है हम चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते हैं न मेरा ध्येय इस सबको रोकना है। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि यदि हम इन बड़ी बड़ी कम्पनियों से उनके जल व्यापार के फल स्वरूप उजड़े हुये गाँवों, खेतों की कहानी, और अनयाय पूर्ण प्रणाली की चर्चा मैत्री पूर्ण ढंग से करें तो उनसे जल्दी उत्तर की तथा उस क्षेत्र के लाभ की अधिक सम्भावनाये बढ़ जाती है। सरकार की अनयाय पूर्ण नितियों से लड़ने में कुछ हासिल नहीं होने का लाभ हमें और सरकार से लड़ने बहुत अधिक समय लग जायेगा वह अलग नियम बन भी गये तो लागू कौन करेगा। एक बिचार हमारे मन में आया है क्यों न हम इन मल्टीनेशनलस को यह अनुमति दे दें कि उन्हें सिर्फ समुद्र के पानी को ही साफ करके बोतल में बेचने की इजाजत होगी। यह तकनीक हमारे देश में आयेगी जो उन कम्पनियों के पास है तथा साधन भी और हमारा पानी भी चोरी नहीं होगा हो हमारे पास कमी में है, इस दिशा में बहुत अनुसंधान की आवश्यकता है और पंयास किया जाय कि सौर ऊर्जा यह काम ही ताकि हमारे और प्रकृतिक साधनों का अपव्यय न हो।

इस समस्या को सुलझाने के लिये पानी के संकलन, संचालन और व्यय सम्बन्धी जिस दूरदर्शिता व पुंजीपतियों का सहयोग, वैज्ञानिकों के परामर्श की आवश्यकता है, ऐसी सम्यक योजना की आशा वर्तमान भारत सरकार से हम कर सकते हैं क्या? पर चाह करनी पड़ेगी। अमरीका में जहाँ हम रहते हैं मिचिगन में ही पूरी दुनिया के मीठे पानी का 20% चार बड़ी बड़ी झीलों में है। पर यहाँ के लोग साल में करीब सौ करोड़ का बोतल पानी खरीदते हैं क्योंकि उनकी जानकारी में नल का पानी गन्दा है। लेकिन सरकार और जनता ने यहाँ पर सोचना शुरू कर दिया है कि पानी के वे रोक टोक तरीकों को रोक जाय परमिट दिये जाय जितना पानी कोई कम्पनी के रूप में, किसानों की खेती में काम के लिये निकाला जाय, इसका समाज की समपदा मान कर उससे पैदा हुये मुआवजे को उसी अनुपात में समाज को समाज की सम्पत्ती मान के उसे वापिस दिया जाय।

क्या हमारे देश में यह नहीं हो सकता है कि किसान जो एक पम्प खरीद सकता है और उसे चलाने के लिये डजिल या बिजली खरीद के उसे दिन रात चलाकर जितना पानी जमीन से निकाल सकता है। यह पानी वह सिर्फ अपने लिये ही नहीं निकालता बरन बेचता भी है। उसे किसने दिय यह हक? उसके इस कर्म का आस पास के गरीब किसानों की जमीनों पर भी पड़ता है। उनको अपनी जमीन पर अपनी फसल के लिये और अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। क्या यह पम्प बाला अमीर ज्यादा लगान देता है या अपनी आनदनी को अपने पड़ोसी के साथ वाटता है। नहीं तो क्यों नहीं क्या यह अन्याय नहीं है? हमने अपनी यात्रा के दौरान कई ऐसे हरे भरे खेत देखे हैं जो 20 25 सूखे खेतों से घिर अपनी कहानी रो रहे थे। क्या पंचायतें इसे रोक सकती हैं?

एक और स्वतंत्र विचार मुझे अहमदाबाद में देखने के बाद आया। हर बड़े शहर के बीच में चाहे यह गुजरात हो या राजस्थान एक बड़ा नाला शहर के बीचों बीच दुर्गन्ध उड़ाता हुआ एक अजरगर की तरह पसरा हुआ है क्यों न इस पानी को हम पाईपो के जरिये शहर से दूर जहाँ आवादी न हो और कृषि की सम्भावना हो ले जाया जाए। इस गन्दे पानी का दो तरह से निदान हो सकता है या तो सब्जी के बागों में या फिल्टर करके जमीन में रिचार्ज कर दिया जाय और एरिणेशन के बाद इसको स्थानिय नदियों में डाल दिया जाए। पर इस बिश्य में बहुत अनुसंधान की आवश्यकता है। पहले तो इन नालों को बन्द करके पाईप डालने होंगे। फिर जैसे साफ पानी को गाँव से शहर लाया जाता उसी तरह गन्दे पानी को शहर से गाँवों की तरफ ले जाया जाए। पर इस गन्दे पानी को ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ कृषि के लिये अनय साधन न हो। इस पूरी स्कीम में जो जैसा पानी लेगा उसका वैसा ही मूल्य देना होगा, साफ तो ज्यादा मूल्य देना होगा। इस काम को करने के लिये स्वायत्त बोर्ड हो न कि सरकार करे हर काम को अपने उपर ओढ़ ले, सरकार का काम जन हित में नियम बनाना व उनको लागू करना होता है। हम लोग क्या इतनी कम अकल के हैं कि बिना सरकारी हस्ताक्षर के कोई काम नहीं कर सकते हैं?

पानी बचाने के बहुत से उपायों में एक है नहाने के पानी में कमी करना, पानी से शरीर की सफाई की जाय उसको व्यर्थ न बहाया जाए। साबुन का इस्तेमाल तलाब पर नहीं किया जाना चाहिये न नहाने में ही क्योंकि इस तरह इस्तेमाल किया हुआ पानी कृषि के लायक नहीं रहता है और मछलियों के लिये भी अच्छा नहीं होता है। अगर आप बदन को साफ करना चाहते हैं तो गर्म पानी को बाल्टी में लो फिर उसमें एक छोटा तौलिया डुबोकर शरीर को मले तो बदन ज्यादा साफ होगा बजाय साबुन के इस्तेमाल से। शरीर रगड़कर नहाने से मरी हुई सूखी त्वचा हट जाती है और हमारे रन्ध्र खुल जाते हैं। रगड़ने से सफाई भी होगी और मालिश भी, बाद में यह पानी पेड़ों को सींचने में भी काम में लिया जा सकता है। हम गत कई सालों से साबुन का इस्तेमाल नहाने के लिये नहीं करते हैं। जितने अधिक मकान शहरों में गाँवों में बन रहे हैं उससे वर्षा का पानी जमीन में न जाकर नालियों में बह जाता है और नालियाँ नालों में बदल जाती हैं। नियम होना चाहिये की हर नये मकान में राजस्थान के तरह वर्षा के पानी को जमा करने का टैंक हो। ताकि इस पानी को गैर खाने की हर जगह जैसे बगीचों में, इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे पानी को शहर में लान वगैरहा में इस्तेमाल करना पानी का अपव्यय है। इसको रोकना चाहिये। यदि वर्षा का पानी ठीक से जमा के लिया जाय तो पखाने में फ्लस के लिये प्रयोग में करा जा सकता है। इसी तरह नहाने के बाद बाल पानी भी फ्लस के काम में लिया जा सकता है।

आवश्यकता है ऐसे छोटे प्लान्ट्स की जो पखाने को खाद में बदल सके। इसके लिये तकनीक है या स्थानिय बनाई भी जा सकती है। हमारे देश में जेवल वर्षा का आधा ही पानी जमीनमें जाता है बाकी नलियों में या सड़क के किनारे गड्ढों में कीचड़ की तरह सड़ता रहता है, या बाढ़ों के पानी के रूप में समुद्र से जल्दी ही जा मिलता है। साईंस की मदद से हम इस आधे पानी को सीधे समुद्र में जाने से रोक सकते हैं। जमीन के अन्दर बड़े टैंक बनाकर। पर यह काम सहयोगिक क्षेत्र में हो सरकार न करे। क्योंकि व्यापारी बगै अपने उत्थान के लिये अधिक प्रयत्नशील व सज्ज होना है। हमने बहुत से नये नये अच्छे काम गाँवों में होते हे देखे हैं पर एक जगह जो काम 1 रहा दूसरे प्रान्त में उसका लोगो को पता भी नहीं है। अच्छी विकास की खबरे कछुये की गति से चलती है पर बुरी प्रकाश की गति से चलती है। जरूरत है अच्छे कामों की खबर फैलाने की न कि हर बात में सरकारसे उलझने की। डाक्टर सुन्दरेसन एक गाँव को बदल डाला या नानाजी देशमुख ने चित्रकूट के आस पास करीब पांच सौ मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के गाँवों को बदल दिया पर हम इस विकास को हर भारत के गाँवों में क्यों नहीं ले जा सकते हैं ?

समय की माँग को देखते हुये पानी की बचत के लिये उपयोगी तरीके ईजाद करने के लिये जन आवाहन करना चाहिये वरना मुद्दों को लेकर सरकार के साथ तकरार में समय, धन, व शक्ति तीनों ही की हानि होगी कैसे करेंगे कुछ सुझाव हैं जो नीचे लिखे हैं।

- अगर हम भारत में सुधार चाहते हैं तो पानी की बचत सम्बन्धित समाचारों को, समाचार पत्रों में मुख्य स्थान देना होगा करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुज्ञान, यह विचार भारत के राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी का है
- मार धाड़ की खबरे जो आतंक ही फैलाती हैं उन्हें पांशवे या छटे पृष्ठ पर ही ईथान मिलना चाहिये जैसा ईजराइल में होता है
- स्फाई में पानी का कम से कम ईस्तेमाल होना चाहिये जैसे वैक्यूम के सहारे से सफाई की जाय यहाँ तक इसके सहारे से फ्लश भी साफ किये जाने लगे हैं इन उपकरणों को सूर्य ऊर्जा या डजिल, हवाई मिलो के जरिये से चलाया जा सकता है नई नई सम्भावनाये पैदा होगी
- हमें अपने दृष्टिकोण आशाजनक रखने चाहिये निराशा से तो अच्छा है तो हमें अवश्य ही सफलता हाथ लगेगी और हमारा उत्साह ही बढ़ेगा
- शहरों में गाँवों में सार्वजनिक नलों पर होने वाली बरबादी को रोकने के लिये समूहिक प्रार्पटी की देखभाल करना हम सभी का काम है और इसके लिये समूहिक जागरूकता लानी होगी। पर उनके आस पास जो कीचड़ के लिये सोकिंग पिट का निर्माण किया जाय फिर उसे रेत व कंकड़ों से भर दिया जाय ताकि कीचड़ न हो। जब हाथ पम्प के लिये खोदा जाय उसी समय इसका भी प्रोविजन रक्खा जाय
- पानी राष्ट्र की सम्पति है और इसकी मात्रा सीमित है और उसकी बरबादी को रोकना हम सबकी सामूहिक व एकाकी जिम्मेदारी होनी चाहिये
- कोई चीज मुफ्त नहीं होती पर यदि आप सरकार से कराना चाहते हैं तो अवश्य ही इसका तीन गुना मूल्य देना होगा जनमानस को अप्रयत्क्ष रूप में
- आकड़ों से जनता को अबगत काराया जाय कि किन किन तरीकों से कितने पानी की बचत हो चकी है अब तक। समय समय पर इन खबरों से लोग उत्साहित होकर नियमों का पालन अधिक करेंगे पानी को बचाने के लिये
- गरीबों को गरीबी से उपर उठाना है तो उनमें आत्म सम्मान जगाना होगा, उन नियमों को हटाना होगा जो उन्हें गरीबी से उपर उठने में बाधा डालते हैं क्योंकि यदि मुझे कुछ बताओ शायद मुझे याद रहे पर यदि मुझे अपने साथ लेकर चलो या काम में लगाओ तो मैं शायद ही भूलू

सरकारी कर्मचारियों को समाज के जन मानस की सेवा की ट्रेनिंग दी जाय कि उनकी सेवाये जनता के लिये हैं न की जनता पर राज करने के लिये। सरकारी अनुदानों को ऋण के रूप में दिया जाय जिससे लोगों में आत्म सम्मान व विश्वास पैदा हो कि हम अपनी जिन्दगी स्वयं चलाने योग्य हैं।

रश्मि उमेश रोहतगी

14 अप्रैल 2002

Umesh Rashmi Rohatgi 24161 Nilan Drive Novi MI 48375 Ph: (248) 471-5786

Web page : www.ruohatgi.com Email: ruohatgi@yahoo.com